सी.एन. रामप्पा गौड़ा

बनाम

वी.सी.सी. चंद्रेगौड़ा (मृत) जरिये विधिक प्रतिनिधि और अन्य

(2012 की सिविल अपील संख्या 3710)

अप्रैल 23, 2012

[टी.एस. ठाकुर और ज्ञान सुधा मिश्रा, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश 8, नियम 10- लिखित कथन दाखिल न करना - न्यायालय का कर्तव्य-अभिनिर्धारित-ऐसे मामले में जहां लिखित कथन दाखिल नहीं किया गया है, न्यायालय को आदेश 8 नियम 10 के तहत कार्यवाही में थोड़ा अधिक सतर्क रहना चाहिए और निर्णय पारित करने से पहले, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भले ही वाद में दिए गए तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया हो, फिर भी वाद में दिए गए तथ्य को साबित करने की आवश्यकता के बिना कोई निर्णय और डिक्री पारित नहीं की जा सकती है-यह केवल तभी जब न्यायालय अभिलिखत कारणों से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसे वादी की और से प्रतिवादी द्वारा मानी गई स्वीकारोक्ति के मद्देनजर साबित करने की आवश्यकता है, तो न्यायालय आसानी से उस प्रतिवादी के खिलाफ निर्णय और डिक्री पारित कर सकता है जिसने लिखित कथन दाखिल नहीं किया है-लेकिन, यदि वादपत्र स्वयं इंगित करता है कि वादपत्र से उत्पन्न

होने वाले मामले में तथ्य के विवादित प्रश्न शामिल हैं, जो दो संस्करणों को जन्म देते हैं, तो तथ्यात्मक विवाद को निपटाने के लिए वादी को तथ्यों को साबित करने का निर्देश दिए बिना न्यायालय के लिए एकपक्षीय रिकॉर्ड करना सुरक्षित नहीं होगा। मौजूदा मामले में, विचारण न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए मुकदमे पर फैसला सुनाया कि कैसे वादी संपत्ति में आधे हिस्से का हकदार था-यह प्रकृति में पूरी तरह से गूढ़ था जिसमें विचारण न्यायालय ने इस बात की गंभीरता से जांच नहीं की कि वादी द्वारा परिवार की संयुक्तता की अभिवाक् के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र कैसे साबित हुआ-दावा कोई सबूत नहीं है और इसलिए, वादी पर यह साबित करने का भार है कि संपत्ति उसके पास थी अतीत में विभाजन नहीं किया गया है, भले ही इसके विपरीत कोई लिखित कथन या खंडन का कोई सबूत न हो-विचारण न्यायालय ने यह अनुमान लगाकर स्पष्ट रूप से एक गलत दृष्टिकोण अपनाया कि केवल इसलिए कि इनकार या खंडन का कोई साक्ष्य नहीं था, वादी का मामला साबित हुआ माना जा सकता है-विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को रद्द करने में उच्च न्यायालय कानूनी रूप से उचित था और प्रतिवादी/प्रत्यर्थी को लिखित कथन पेश करने की अनुमति देने के बाद मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए विचारण न्यायालय में भेजने की सीमित सीमा तक अपील की अनुमति दी गई -हालाँकि, चूंकि विभाजन के मुकदमे के निस्तारण को मुकदमे की लंबी पुर्नसुनवाई में घसीटा गया है, वादी/ अपीलकर्ता को प्रतिवादी/ प्रत्यर्थी द्वारा

शीघ्रता से भुगतान की जाने वाली सांकेतिक व्यय के रूप में पच्चीस हजार रुपये की राशि देकर समानता और निष्पक्षता के पैमाने को संतुलित करना कानूनी रूप से न्यायसंगत और उचित है। पुन: सुनवाई का निर्देश देने वाला उच्च न्यायालय का विवादित आदेश उसके बाद ही प्रभावी होगा।

अपीलकर्ता ने जमीन-जायदाद के बंटवारे और अलग कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया था, जो उसके मामले के अनुसार संयुक्त परिवार की संपत्ति थी। प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं को नोटिस दिया गया था जिसके जवाब में उनके वकील ने वकालतनामा दाखिल किया था। हालाँकि, कई अवसरों के बावजूद, प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं द्वारा कोई लिखित कथन पेश नहीं किया गया और बाद में, विचारण न्यायालय ने वादी-अपीलकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया। वादी ने कुछ दस्तावेजों के साथ शपथ पत्र के माध्यम से अपना साक्ष्य दाखिल किया। अपने मामले के समर्थन में वादी द्वारा पेश की गई दलीलों और एकपक्षीय साक्ष्य के आधार पर, विचारण न्यायालय ने वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में मुकदमे का फैसला सुनाया और उसे आधे हिस्से की सीमा तक विभाजन की डिक्री का हकदार माना। ज़मीन जायदाद में इसके बाद प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया और मामले को दोबारा सुनवाई और मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए विचारण न्यायालय को भेज दिया। प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं को लिखित कथन

दाखिल करने और दस्तावेज प्रस्तुत करने की भी स्वतंत्रता दी गई। विचारण न्यायालय को मुकदमे का निपटारा गुणावगुण पर करने का निर्देश दिया गया। विभाजन की डिक्री, जो वादी-अपीलकर्ता को पहले ही उसके पक्ष में निष्पादित कर दिया गया था, मुकदमे की पुनः सुनवाई के परिणाम के अधीन बनाया गया।

वर्तमान अपील में जिन प्रश्नों के निर्धारण की आवश्यकता थी वे थे:

1) क्या उच्च न्यायालय ने मुकदमे की दोबारा सुनवाई के लिए विचारण न्यायालय को निर्देश देकर और प्रतिवादियों को कोई उचित और कानूनी रूप से ठोस कारण बताए बिना लिखित कथन और दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति देकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, खासकर जब प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं को स्वीकारोक्तिपूर्वक सम्मन जारी किया गया था और विचारण न्यायालय में उनके वकील द्वारा उनका विधिवत प्रतिनिधित्व भी किया गया था (ii) क्या जिन प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कई अवसरों के बावजूद लिखित कथन दाखिल नहीं करने का विकल्प चुना था, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा लिखित कथन पेश करने का नया अवसर देने और पुन: सुनवाई करने का आदेश दिया जा सकता था, जिसके परिणामस्वरूप वादी-अपीलकर्ता को अपने पक्ष में डिक्री के फल का आनंद लेने में देरी और पूर्वाग्रह हुआ और (iii) क्या विचारण न्यायालय जिसके समक्ष प्रतिवादी

बार-बार अवसरों के बावजूद लिखित कथन पेश करने से विफल रहे, वादी के मामले की गुणावगुण पर विचार किए बिना और वादी को अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिए बिना और किसी भी साक्ष्य की विवेचना किए बिना या अनुपस्थिति के बावजूद सीधे वादी के पक्ष में डिक्री पारित की जा सकती है। लिखित बयान के आधार पर, विचारण न्यायालय को वादी के मामले की गुणावगुण की सूक्ष्मता से विवेचना करते हुए मुकदमे की सुनवाई करनी चाहिए और वादी को अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का निर्देश देना चाहिए, जिसमें वादी द्वारा दिए गए साक्ष्य के महत्व की जांच की जाए।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित कियाः

1.1. वादी-अपीलकर्ता ने अपने मामले को केवल शपथ पत्र जो उसने फाइल किया था, के आधार पर साबित करने की मांग की है कि वादग्रस्त संपत्ति एक संयुक्त परिवार की संपत्ति थी, और यह स्थापित करने के लिए कोई भी मौखिक या दस्तावेजी सबूत पेश करने में विफल रहा है कि संपत्ति संयुक्त प्रकृति की थी। भले ही वादी-अपीलकर्ता का मामला सही था, विचारण न्यायालय के लिए वादी के मामले की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण था, ताकि उसे यह निर्देश दिया जा सके कि वह विश्वसनीयता के योग्य कुछ दस्तावेजी सबूत पेश करे कि जिस संपत्ति का विभाजन किया जाना है, वह प्रकृति में संयुक्त थी। लेकिन ऐसा लगता है कि

विचारण न्यायालय ने वादी के मामले पर भरोसा करते हुए केवल वादी द्वारा दायर शपथ पत्र पर भरोसा किया है, जो कम से कम कुछ दस्तावेजी सबूतों पर परीक्षण करने के लिए उपयुक्त था, भले ही वह एकपक्षीय तरीके से हो। विचारण न्यायालय द्वारा आंखों पर पट्टी बांधकर शपथ पत्र पर भरोसा केवल इस आधार पर किया गया कि प्रतिवादी लिखित कथन दाखिल करने में विफल रहा है, यह मुकदमे के दंडात्मक उपचार के समान होगा और परिणामी डिक्री उस डिक्री के समान होगी जो किसी दंडात्मक प्रकृति की डिक्री से कम नहीं होगी। [पैरा 13] [466- एफ- एच; 467- ए-बी]

1.2. लिखित कथन दाखिल न करने और मुकदमे की सुनवाई के लिए आगे बढ़ने का प्रभाव स्पष्ट रूप से मुकदमे के निपटारे में तेजी लाना है और यह दंडात्मक प्रकृति का नहीं है, जिसमें प्रतिवादी को मुकदमे की सुनवाई करके लिखित कथन दाखिल न करने के लिए एक यांत्रिक तरीक से डिक्री पारित करके दंडित किया जाना है। ऐसे मामले में जहां लिखित कथन दाखिल नहीं किया गया है, न्यायालय को आदेश 8 नियम 10 सीपीसी के तहत आगे बढ़ने में थोड़ा अधिक सतर्क रहना चाहिए और निर्णय पारित करने से पहले, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भले ही वाद में दिए गए तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया है, वाद में बताए गए तथ्य को साबित करने की आवश्यकता के बिना निर्णय और डिक्री संभवतः पारित नहीं की जा सकती। ऐसा तभी होता है जब न्यायालय अभिलिखित

कारणों से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसे प्रतिवादी द्वारा मानी गई स्वीकारोक्ति के मद्देनजर वादी को साबित करने की आवश्यकता है, न्यायालय आसानी से प्रतिवादी के खिलाफ निर्णय और डिक्री पारित कर सकता है। जिन्होंने लिखित कथन दर्ज नहीं कराया है। लेकिन अगर वादी स्वयं इंगित करता है कि मामले में तथ्य के विवादित प्रश्न शामिल हैं, जो वादी के दो संस्करणों को जन्म देता है, तब न्यायालय के लिए वादी को तथ्यों को साबित करने का निर्देश दिए बिना एकपक्षीय निर्णय दर्ज करना सुरक्षित नहीं होगा। जिससे तथ्यात्मक विवाद का निपटारा किया जा सके। उस स्थिति में, एकपक्षीय फैसले से ऐसा प्रतीत हो सकता है कि उसने मुकदमे का फैसला शीघ्रता से कर दिया है, लेकिन यह अंततः अपील के बाद अपील की कई परतों को जन्म देता है जो अंततः मुकदमे के निपटान में देरी को बढ़ाता है जिससे कार्यवाही की बहुलता को बढ़ावा मिलता है जो त्वरित सुनवाई के कारण शायद ही बढ़ावा देता। हालाँकि, यदि न्यायालय का यह स्पष्ट मानना है कि बिना किसी सबूत के भी वादी का मामला प्रथम दृष्टया दोषमुक्त है और प्रतिवादी का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से डिक्री पारित करने में देरी करने की एक टालमटोल रणनीति है, तो उचित मामलों में भी निर्विरोध डिक्री पारित करना उचित होगा। इस तरह के मामले की प्रकृति अंततः क्या होगी, इसे विचारण न्यायालय की बुद्घिमता और उचित विवेक पर छोड़ना होगा, जिसने मुकदमे की सुनवाई की है। [पैरा 14] [467- सी- एच; 468- ए- बी]

बलराज तनेजा और अन्य। वी. सुनील मदान और अन्य, (1999) 8 एससीसी 396: 1999 (2) सप्ल। एससीऔर 258; कैलाश बनाम नन्हकू और अन्य। (2005) 4 एससीसी 480: 2005 (3) एससीऔर 289- पर भरोसा किया गया।

2. मौजूदा मामले में, विचारण न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए मुकदमे पर फैसला सुना दिया कि वादी संपत्ति में आधे हिस्से का हकदार कैसे है। यह पूरी तरह से गूढ़ प्रकृति का है, जिसमें विचारण न्यायालय ने गूढ़ता से जांच नहीं की कि वादी के द्वारा परिवार की संयुक्तता के अभिवचनों के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र, जो प्रदर्श पी 1 से प्रदर्श पी 10 पर आधारित है, वादग्रस्त संपत्ति को संयुक्त संपत्ति दर्शित करने वाले दस्तावेजों की प्रकृति की विवेचना किए बिना कैसे साबित है। प्रदर्श पी-1 से पी-10 अर्थात एटलस, टिपनी बुक, और.और. पक्का पुस्तक, निपटान अकरबंद, बिक्री विलेख आदि प्रारंभिक विलेख है। विचारण न्यायालय ने हालांकि इन दस्तावेजों पर भरोसा किया, लेकिन उसने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि इन दस्तावेजों पर विश्वास क्यों किया गया है, बिना यह बताए कि यह इस दलील को कैसे साबित करता है कि संपत्ति हमेशा प्रकृति में संयुक्त रही थी और पक्षकारों के बीच कभी भी बंटवारा नहीं हुआ। भले ही विचारण न्यायालय ने यह अनुमान लगाने के लिए इन दस्तावेजों पर भरोसा किया कि संपत्ति संयुक्त प्रकृति की थी, लेकिन वह इस बात का कोई कारण अभिलिखित करने में विफल रहा कि

क्या संपत्ति का कभी भी सहदायिकों के बीच विभाजन नहीं हुआ था। यह एक सर्वमान्य कानूनी सिद्धांत है कि दावा कोई सबूत नहीं है और इसलिए, वादी पर यह साबित करने का भार है कि संपत्ति का विभाजन अतीत में नहीं किया गया था, भले ही इसके विपरीत कोई लिखित कथन या खंडन का कोई साक्ष्य न हो। विचारण न्यायालय ने यह अनुमान लगाकर स्पष्ट रूप से एक गलत दृष्टिकोण अपनाया है कि केवल इसलिए कि इनकार या खंडन का कोई साक्ष्य नहीं था, वादी के मामले को साबित माना जा सकता है। इसलिए, विचारण न्यायालय को वादी-अपीलकर्ता की याचिका स्वीकार करते समय कारण अभिलिखित करना चाहिए था, भले ही वह एकपक्षीय साक्ष्य पर आधारित हो कि वादी वाद की संपत्ति की संयुक्तता को साबित करने में सफल रहा था, जिसके आधार पर डिक्री की गई थी। विभाजन का प्रस्ताव उनके पक्ष में पारित किया जा सकता था। [पैरा 15] [468- सी-एच; 469- ए]

3. उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को रद्द करने और प्रतिवादी- उत्तरदाता को लिखित कथन पेश करने की अनुमति देने के बाद मामले को विचारण न्यायालय में नए सिरे से सुनवाई के लिए भेजने की सीमित सीमा तक अपील की अनुमति देना कानूनी रूप से उचित था। हालाँकि, यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि वादी/अपीलकर्ता को अपनी ओर से बिना किसी गलती के भी प्रतिवादी के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में उलझने के लिए मजबूर किया

गया है, जिससे इस न्यायालय के समक्ष अपील को जन्म दिया है, हालाँकि प्रतिवादी/उत्तरदाता कई अवसरों के बावजूद लिखित कथन दाखिल करने में और वादी गवाहों का प्रतिपरीक्षण करने में असफल रहे-लेकिन एक बार जब वादी/ अपीलकर्ता के पक्ष में आधे हिस्से के बंटवारे का आदेश पारित हो गया, तो प्रतिवादी/उत्तरदाता ने तुरंत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करके इसे चुनौती दी। चूंकि विभाजन के मुकदमे का निपटारा अब मुकदमे की लंबी पुनर्सुनवाई में घसीटा गया है, इसलिए सांकेतिक लागत के रूप में पच्चीस हजार रुपये की राशि का अवार्ड देकर समानता और निष्पक्षता के पैमाने को संतुलित करना कानूनी रूप से न्यायसंगत और उचित है। प्रतिवादी/उत्तरदाता द्वारा वादी/ अपीलकर्ता को शीघ्रता से भुगतान किया जाना चाहिए क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई का निर्देश देने वाला आक्षेपित आदेश उसके बाद ही प्रभावी होगा। [पैरा 16] [469- बी- एफ]

केस कानून संदर्भ

1999 (2) सप्ल. एससीऔर 258 का पैरा 10,

2005 (3) एससीऔर 289 का पैरा 11 को आधार बनाया गया।

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3710/2012.

कर्नाटक उच्च न्यायलाय के बेंगलुरु पीठ के और.एफ.ए. नंबर 2004 की संख्या 597 में निर्णय और आदेश दिनांक 05.10.2010 से

और.एस. हेगड़े, चंद्र प्रकाश, अश्वनी गर्ग, पी.पी. सिंह अपीलार्थी की ओर से।

टी.वी. रत्नम उत्तरदाताओं की और से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

ज्ञान सुधा मिश्रा, जे. 1. प्रश्नगत आदेश दिनांक 05.10.2010 जो कर्नाटक उच्च न्यायालय की बेंगलुरु पीठ द्वारा और.एफ.ए. नंबर 597/2004 में पारित किया गया था। इस अपील में विचाराधीन है। जिसके लिए वादी/अपीलकर्ता की प्रार्थना पर विशेष अनुमति याचिका मंजूर की गई। इस आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने सिविल जज (सीनियर डिविजन) चिकमंगलूर द्वारा वादी/अपीलकर्ता के पक्ष में पारित विभाजन के निर्णय और डिक्री दिनांक 28.01.2004 को अपास्त कर दिया और मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए अपील को विचारण न्यायालय में भेज दिया गया। इसमें प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर लिखित कथन दाखिल करने और दस्तावेज पेश करने की भी स्वतंत्रता दी गई है और विचारण न्यायालय को विधि के अनुसार गुण-दोष के आधार पर मुकदमे का निपटारा छह महीने की अवधि में करने का निर्देश दिया गया है। हालाँकि,

विभाजन की डिक्री, जिसे वादी-अपीलकर्ता ने पहले ही अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया था, को मुकदमे की पुनः सुनवाई के परिणाम के अधीन कर दिया गया था।

2. (i) इस अपील में जिस मूल प्रश्न के निर्धारण की आवश्यकता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने मुकदमे की दोबारा सुनवाई के लिए विचारण न्यायालय को निर्देश देकर और प्रतिवादियों को कोई उचित और कानूनी रूप से स्थायी कारण बताए बिना लिखित कथन और दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति देकर अपने अधिकार क्षेत्र से आगे निकल गया है। विशेष रूप से तब जब बचाव पक्ष- प्रतिवादियों द्वारा सम्मन स्वीकार कर लिया गया था और विचारण न्यायालय में उनके वकील द्वारा उनका विधिवत प्रतिनिधित्व भी किया गया था?

(ii) आगे का प्रश्न जो इस मुद्दे से संबंधित है, वह यह है कि क्या जिन प्रतिवादियों- उत्तरदाताओं ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कई अवसरों के बावजूद लिखित कथन दाखिल नहीं करने का विकल्प चुना था, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा लिखित कथन दाखिल करने के लिए नया अवसर दिया जा सकता है और पुनः सुनवाई के आदेश के परिणामस्वरूप वादी-अपीलकर्ता को उसके पक्ष में डिक्री के फल का आनंद लेने में देरी और पूर्वाग्रह होता है?

(iii) एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहां उठता है और अक्सर विचारण न्यायालय के सामने उठता है, वह यह है कि क्या विचारण न्यायालय, जिसके समक्ष प्रतिवादी बार-बार अवसरों के बावजूद लिखित कथन दाखिल करने में विफल रहे, गुणावगुण के बिना सीधे वादी के पक्ष में डिक्री पारित कर सकता है। वादी के मामले के गुण-दोष और वादी को अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिए बिना और किसी भी साक्ष्य की विवेचना किए बिना या लिखित कथन की अनुपस्थिति के बावजूद, वादी के मामले में विचारण न्यायालय को मुकदमे की गुणावगुण पर सूक्ष्मता से विवेचना करते हुए मुकदमे की सुनवाई करनी चाहिए। वादी को अपने मामले के समर्थन में दिए गए साक्ष्य के वजन की जांच करने के लिए वादी को साक्ष्य पेश करने का निर्देश देता है?

3. इससे पहले कि हम इस अपील में शामिल उपरोक्त प्रश्नों की विवेचना करें, अनुमति दिए जाने के बाद इस अपील को जन्म देने वाले मामले की कुछ मुख्य विशेषताओं और तथ्यों को रिकॉर्ड करना आवश्यक प्रतीत होता है।

4. वादी-अपीलकर्ता ने 13 एकड़ 20 गुंटा की भूमि संपत्ति के विभाजन और अलग कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया था, जो उसके मामले के अनुसार एक संयुक्त परिवार की संपत्ति थी, जिसमें विभाजन नहीं हुआ था और चूंकि प्रतिवादी-उत्तरदाता अनुसूचित संपत्ति में

वादी के आधे हिस्से के अलग कब्जे के और विभाजन की व्यवस्था करने में विफल रहे थे, वादी को विभाजन के लिए मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया गया था। वादपत्र में यह भी कहा गया था कि प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं ने वादी-अपीलकर्ता को कोई हिस्सा दिए बिना संपत्ति का आपस में बंटवारा कर लिया था। वादी- अपीलकर्ता ने प्रतिवादी-उत्तरदाता को दिनांक 24.05.1999 को एक कानूनी नोटिस भेजा, जो उन पर विधिवत तामील हुआ, जिसके जवाब में प्रतिवादी अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हुए और 10.07.1999 को वादी के दावे को खारिज करते हुए जवाब भेजा। वादी-अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों- उत्तरदाताओं के जवाब को ध्यान में रखते हुए विभाजन और अलग कब्जे के लिए चिकमंगलूर में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत के समक्ष ओएस नंबर 197/2002 वाला मुकदमा दायर किया। उक्त मुकदमे में प्रतिवादी-उत्तरदाताओं को नोटिस दिया गया था जिसके जवाब में उनके वकील द्वारा वकालतनामा दाखिल किया गया था। हालाँकि, कई अवसरों के बावजूद, प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं द्वारा कोई लिखित कथन पेश नहीं किया गया था। चूंकि प्रतिवादी-उत्तरदाता लिखित कथन दाखिल करने में विफल रहे, इसलिए विचारण न्यायालय ने वादी को साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिया। वादी ने कुछ दस्तावेजों के साथ हलफनामे के माध्यम से अपना साक्ष्य दाखिल किया, जिन्हें प्रदर्श पी-1 से पी-10 के रूप में चिह्नित किया गया था। हालाँकि, वादी से न तो प्रतिवादियों द्वारा जिरह की गई थी और

न ही प्रतिवादियों ने लिखित कथन दाखिल किया था जैसा कि यहाँ पहले ही बताया गया है।

5. चूंकि प्रतिवादियों ने न तो लिखित कथन दाखिल किया और न ही वादी से जिरह की, विद्वान न्यायाधीश ने अपने मामले के समर्थन में वादी द्वारा प्रस्तुत दलीलों और एकपक्षीय साक्ष्य के आधार पर दिनांक 28.01.2004 के फैसले और आदेश के तहत फैसला सुनाया। मुकदमा वादी- अपीलकर्ता के पक्ष में गया और इस प्रकार उसे भूमि संपत्ति में आधे हिस्से की सीमा तक विभाजन की डिक्री का हकदार माना गया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने आगे कहा कि हालांकि प्रतिवादियों को नोटिस दिया गया था और उनके वकील द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया गया था, उन्होंने वादी के मामले को नकारते हुए लिखित कथन दाखिल करने का विकल्प नहीं चुना और इसलिए वादी के मामले पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। तदनुसार, मुकदमे में यह निर्देश देते हुए फैसला सुनाया गया कि वादी-अपीलकर्ता संपत्ति में आधे हिस्से का हकदार होगा।

6. इसके बाद प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं ने औरएफए नंबर 597/2004 के साथ अपील दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष फैसले और डिक्री को चुनौती दी, जिसमें वादी-अपीलकर्ता ने निवेदन किया कि प्रतिवादी-उत्तरदाताओं ने उन पर सम्मन की तामील होने के बावजूद विचारण

न्यायालय के समक्ष कारवाईयों में भाग न लेने और लिखित कथन पेश न करने का कोई वैध और न्यायसंगत कारण नहीं बताया है। लिखित कथन पेश करने की अनुमति मांगने वाली कोई प्रार्थना भी शामिल नहीं थी। उसमें यह भी कहा गया था कि वादी ने विभाजन की प्रारंभिक डिक्री पहले ही निष्पादित करवा ली थी और अनुसूची संपत्ति के आधे हिस्से पर उसका कब्ज़ा हो गया था।

7. उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 30.05.2005 द्वारा वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और निर्देश दिया था कि विचारण न्यायालय अंतिम डिक्री कार्यवाही पूर्ण कर सकता है। हालाँकि, यह देखा गया कि यदि प्रारंभिक डिक्री को प्रभावी किया जाता है और संपत्ति को अंतिम डिक्री कार्यवाही में विभाजित और आवंटित किया जाता है, तो यह अपील के परिणाम के अधीन होगा। इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी नंबर 1 की मृत्यु हो गई, जिसके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाया गया था।

8. अपील पर अंततः उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई अपील में निर्णय और आदेश 05.10.2010 को उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द करते हुए दिया गया था और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए विचारण न्यायालय को

भेज दिया गया था जैसा कि पहले ही यहां बताया गया है। वादी-अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश से व्यथित महसूस किया और इसलिए इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें अनुमति दी गई और मामले की सुनवाई की गई।

9. वादी-अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह की गई दलीलों को दोहराया और तर्क किया है कि प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं को अपना लिखित कथन पेश करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकारों को समाप्त करना चाहिए क्योंकि प्रतिवादियों को सम्मन की विधिवत तामील हुई थी और उनके वकील द्वारा भी प्रतिनिधित्व किया गया था। इसके बावजूद प्रतिवादियों ने लिखित कथन दाखिल नहीं करने का फैसला किया, हालांकि कई अवसर दिए गए थे और उन्होंने लिखित कथन दाखिल नहीं करने का कोई कारण भी नहीं बताया था। आगे यह आग्रह किया गया कि अपील में भी प्रतिवादियों ने मुकदमे की संपत्ति के संयुक्त परिवार की संपत्ति होने के तथ्य पर विवाद नहीं किया है और इसलिए, इसके विपरीत किसी भी सबूत के अभाव में, उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। यह निवेदन किया गया था कि प्रतिवादी इस मामले में सोए रहे और जब वे लिखित कथन दाखिल करने में विफल रहे तो उन्होंने गंभीर त्रुटि कारित की, जिसके लिए प्रतिवादियों द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया था और इसलिए उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को अधिकार

समाप्त होने के बावजूद उन्हें लिखित कथन और दस्तावेज पेश करने की अनुमति और अनुचित छूट देकर त्रुटि कारित की।

10. अपील का विरोध करते हुए, प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं की ओर से यह आग्रह किया गया कि वादी-अपीलकर्ता के मुकदमे का फैसला केवल वादपत्र में दिए गए कथनों के आधार पर किया गया है, जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य है, भले ही मुकदमे का फैसला हो गया हो। लिखित कथन के अभाव में, विचारण न्यायालय को वादी के गवाह से जिरह किए बिना और सबूतों की विवेचना किए बिना मुकदमे पर फैसला नहीं देना चाहिए था और इसलिए, इसे उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से रद्द कर दिया गया है। उनके प्रस्तुतीकरण के इस भाग को विस्तार से बताते हुए, यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय वादी के मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करने और लिखित कथन के अभाव में भी वादी के दावे की सत्यता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए बाध्य था, जो स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अपने विवेक का सही प्रयोग किया है और प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं को अपना लिखित कथन दर्ज करने की अनुमति दी है। उनकी दलील को मजबूत करने के लिए, यह आगे अतिरिक्त निवेदन किया गया कि वादी की जांच करने और दलीलों के कथनों की सत्यता के बारे में खुद को संतुष्ट करने का कर्तव्य न्यायालय पर डाला गया है और विचारण न्यायालय को वादी की जिरह के बिना उसका दावा स्वीकार नहीं करना चाहिए था। अपने तर्कों के समर्थन में

विद्वान अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत बलराज तनेजा और अन्य बनाम सुनील मदान और अन्य (1999) 8 एससीसी 396 पेश किया। बलराज तनेजा (सुप्रा) के मामले में, न्यायालय ने एक ऐसी परिस्थिति पर विचार करते हुए जिसमें प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन पेश नहीं किया गया था, यह माना कि न्यायालय पूर्ण दलीलों के अभाव में या केवल दलीलों की उपस्थिति में भी निर्णय देने के लिए बाध्य है। इस संदर्भ में विद्वान वकील ने विशेष रूप से इस न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया है जो बहुत प्रासंगिक और मूल्यवान है जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया था: -

> "जैसा कि पहले बताया गया है, न्यायालय को प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथन में दिए गए तथ्य को स्वीकार करने पर न्यायालय में दायर वाद में वादी द्वारा बताए गए तथ्यों पर आंख मूंदकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और न ही अदालत को आंख मूंदकर फैसला सुनाना चाहिए क्योंकि प्रतिवादी ने लिखित कथन दाखिल नहीं किया है। ऐसे मामले में, विशेष रूप से जहां प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन दाखिल नहीं किया गया है, अदालत को आदेश 8 नियम 10 सीपीसी के तहत आगे बढ़ने में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णय देते समय उसे यह अवश्य देखना चाहिए कि भले ही वाद में दिए गए तथ्यों काे स्वीकार कर लिया गया है, वादी को वाद में उल्लिखित किसी भी तथ्य

को साबित करने की आवश्यकता के बिना संभवतः उसके पक्ष में निर्णय पारित किया जा सकता है। यह अदालत की संतुष्टि का मामला है और इसलिए, केवल इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसे डीम्ड स्वीकारोक्ति के कारण साबित करने की आवश्यकता है, अदालत आसानी से प्रतिवादी के खिलाफ फैसला सुना सकती है जिसने लिखित कथन दाखिल नहीं किया है। लेकिन अगर वादपत्र स्वयं इंगित करता है कि मामले में तथ्य के विवादित प्रश्न शामिल हैं जिसके संबंध में वादपत्र में ही दो अलग- अलग संस्करण दिए गए हैं, तो अदालत के लिए वादी से तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता के बिना निर्णय पारित करना सुरक्षित नहीं होगा। ताकि तथ्यात्मक विवाद को सुलझाया जा सके। ऐसा मामला आदेश 8 के नियम 5 के उप-नियम (2) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "किन्तु न्यायालय किसी ऐसे तथ्य को साबित किए जाने की अपेक्षा स्वविवेकानुसार कर सकेगा" या आदेश 8 के नियम 10 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "वाद के संबंध में ऐसा आदेश करेगा जो ठीक समझे" द्वारा कवर किया जाएगा।

11. लिखित कथन दाखिल नहीं करने पर प्रतिवादी की ओर से चूक की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि दिवंगत सी.सी. चंद्रेगौड़ा का प्रतिनिधित्व उनके विधिक प्रतिनिधि सी.सी. द्वारा किया गया। हरीश पीलिया के कारण गंभीर बीमारी से पीड़ित था। इस तथ्य को अपील के चरण में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उच्च न्यायालय ने उसी के आलोक में मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए सही तरीके से विचारण न्यायालय को भेज दिया है। प्रतिवादी-उत्तरदाता के विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि यदि प्रतिवादी-उत्तरदाता के लिखित कथन को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति नहीं दी गई तो उच्च न्यायालय का रिमांड आदेश न्यायहित में काम नहीं आएगा। यदि प्रतिवादियों-उत्तरदाताओ को लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति दिए बिना मुकदमा बहाल किया जाता है और पुन: सुनवाई का आदेश दिया जाता है तो इसका कोई भी उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि लिखित कथन दाखिल करना प्रक्रियात्मक कानून द्वारा शासित है और यह माननीय न्यायालय ने कैलाश बनाम नन्हकू और अन्य (2005) 4 एससीसी 480 में अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है:-

> "आदेश 8 नियम 1 सीपीसी के तहत लिखित कथन दाखिल करने के लिए समय-सारिणी प्रदान करने का उद्देश्य सुनवाई में तेजी लाना है न कि सुनवाई को बाधित करना। यह प्रावधान प्रतिवादी पर अयोग्यता की व्याख्या करता है। यह

समय बढ़ाने के लिए अदालत की शक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। हालांकि आदेश 8 नियम 1 सीपीसी के प्रावधान की भाषा नकारात्मक रूप में लिखी गई है, लेकिन यह गैर-अनुपालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दंडात्मक परिणाम को निर्दिष्ट नहीं करती है। यह प्रावधान प्रक्रियात्मक कानून के क्षेत्र में है, यह निर्देशात्मक होनी चाहिए और आज्ञापक नहीं है। आदेश 8 नियम 1 सीपीसी द्वारा प्रदान की गई समय-सारणी से परे लिखित कथन दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की अदालत की शक्ति पूरी तरह से छीनी नहीं गई है।"

12. अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि वादी-अपीलकर्ता जो वादग्रस्त अनुसूचित संपत्ति में अपने हिस्से के कब्जे का दावा करता है, उसे प्रतिप्रेषित के आदेश से किसी भी तरह से पूर्वाग्रहित नहीं किया जाएगा और इसलिए उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं को लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति देकर मामले को विचारण के लिए पुनः सुनवाई हेतु भेजकर बिल्कुल उचित ही किया है। जिसमें संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार के तहत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. यहां ऊपर उद्धृत मामलों के निर्णय के आलोक में, जब हमने वादी- अपीलकर्ता के पक्ष में विभाजन की डिक्री देने वाले विचारण न्यायालय के फैसले और आदेश की जांच की, तो हम देख सकते हैं कि वादी-अपीलकर्ता ने, यह साबित करने के लिए कि, संपत्ति संयुक्त प्रकृति की थी, अपने मामले को केवल अपने द्वारा प्रस्तुत हलफनामे के आधार पर साबित करने की कोशिश की और यह स्थापित करने के लिए कि संपत्ति संयुक्त प्रकृति की थी, कोई भी मौखिक या दस्तावेजी सबूत पेश करने में विफल रहे हैं। भले ही वादी- अपीलकर्ता का मामला सही था, विचारण न्यायालय के लिए वादी के मामले की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण था, ताकि उसे यह निर्देश दिया जा सके कि वह विश्वसनीयता के योग्य कुछ दस्तावेजी सबूत पेश करे कि जिस संपत्ति का विभाजन किया जाना है, वह प्रकृति में संयुक्त थी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा दायर किए गए हलफनामे पर भरोसा करते हुए वादी के मामले पर भरोसा किया है। कम से कम कुछ दस्तावेजी सबूतों के आधार पर परीक्षण किए जाने लायक था, भले ही वह एकतरफा दावा हो। ट्रायल कोर्ट द्वारा आंखों पर पट्टी बांधकर हलफनामे पर भरोसा केवल इस आधार पर किया गया कि प्रतिवादी लिखित कथन दाखिल करने में विफल रहा है, यह मुकदमे के दंडात्मक उपचार के समान होगा और परिणामी डिक्री उस डिक्री के समान होगी जो डिक्री किसी दंडात्मक प्रकृति से कम नहीं होगी।

14. हमें यहां ऊपर दी गई इस न्यायालय की उपयुक्त टिप्पणियों से पर्याप्त सहायता मिलती है, जिसमें कहा गया है कि लिखित कथन दाखिल न करने और मुकदमे की सुनवाई के लिए आगे बढ़ने का प्रभाव स्पष्ट रूप से मुकदमे के निपटान में तेजी लाने के लिए है और प्रकृति में दंडात्मक नहीं है। जिसमें लिखित कथन दाखिल न करने पर वाद का यांत्रिक तरीके से मुकदमा चलाकर डिक्री पारित कर प्रतिवादी को दंडित किया जाना है। हम दोहराना चाहते हैं कि ऐसे मामले में जहां लिखित बयान दाखिल नहीं किया गया है, अदालत को आदेश 8 नियम 10 सीपीसी के तहत आगे बढ़ने में थोड़ा अधिक सतर्क रहना चाहिए और निर्णय पारित करने से पहले, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भले ही वाद के जो तथ्य सामने आए हों, को स्वीकार कर लिया गया माना जाता है, वादपत्र में प्रस्तुत तथ्य को साबित करने की आवश्यकता के बिना निर्णय और डिक्री संभवतः पारित नहीं की जा सकती। ऐसा तभी होता है जब न्यायालय अभिलिखित कारणों से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसे प्रतिवादी द्वारा मानी गई स्वीकारोक्ति के मद्देनजर वादी की और से साबित करने की आवश्यकता है, न्यायालय आसानी से प्रतिवादी के खिलाफ निर्णय और डिक्री पारित कर सकता है। जिन्होंने लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कराया है। लेकिन, यदि वादपत्र स्वयं इंगित करता है कि वादपत्र से उत्पन्न होने वाले मामले में तथ्य के विवादित प्रश्न शामिल हैं, जो स्वयं दो संस्करणों को जन्म देते हैं, तो न्यायालय के लिए तथ्यात्मक विवाद को

निपटाने के लिए, वादी को साबित करने का निर्देश दिए बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करना सुरक्षित नहीं होगा, उस स्थिति में, एकपक्षीय फैसले से ऐसा प्रतीत हो सकता है कि उसने मुकदमे का फैसला शीघ्रता से कर दिया है, लेकिन यह अंततः अपील के बाद अपील की कई परतों को जन्म देता है जो अंततः मुकदमे के निपटान में देरी को बढ़ाता है जिससे कार्यवाही की बहुलता को बढ़ावा मिलता है जो त्वरित सुनवाई का कारण शायद ही बढ़ावा देता है हालाँकि, यदि न्यायालय का स्पष्ट मानना है कि बिना किसी सबूत के भी वादी का मामला प्रथम दृष्टया दोषमुक्त है और प्रतिवादी का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से डिक्री पारित करने में देरी करने के लिए एक विलंबकारी रणनीति है, उचित मामलों में एक निर्विरोध डिक्री पारित करना भी उचित होगा। इस तरह के मामले की प्रकृति अंततः क्या होगी, इसे विचारण न्यायालय के बुद्घिमता और उचित विवेक पर छोड़ना होगा, जिसने मुकदमे की सुनवाई की थी।

15. जब हमने ऊपर बताई गई बातों के आधार पर तत्काल मामले की जांच की, तो हमने देखा कि विचारण न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए मुकदमे पर फैसला सुना दिया कि वादी संपत्ति में आधे हिस्से का हकदार कैसे है। यह पूरी तरह से गूढ़ प्रकृति का है, जिसमें विचारण न्यायालय ने गूढ़ता से जांच नहीं की कि वादी के द्वारा परिवार की संयुक्तता के अभिवचनों के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र, जो प्रदर्श पी 1 से प्रदर्श पी 10 पर आधारित है, वादग्रस्त संपत्ति को संयुक्त संपत्ति

दर्शित करने वाले दस्तावेजों की प्रकृति की विवेचना किए बिना कैसे साबित है। प्रदर्श पी-1 से पी-10 अर्थात एटलस, टिपनी बुक, और.और. पक्का पुस्तक, निपटान अकरबंद, बिक्री विलेख आदि प्रारंभिक विलेख है। विचारण न्यायालय ने हालांकि इन दस्तावेजों पर भरोसा किया, लेकिन उसने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि इन दस्तावेजों पर विश्वास क्यों किया गया है, बिना यह बताए कि यह इस दलील को कैसे साबित करता है कि संपत्ति हमेशा प्रकृति में संयुक्त रही थी और पक्षकारों के बीच कभी भी बंटवारा नहीं हुआ। भले ही विचारण न्यायालय ने यह अनुमान लगाने के लिए इन दस्तावेजों पर भरोसा किया कि संपत्ति संयुक्त प्रकृति की थी, लेकिन वह इस बात का कोई कारण अभिलिखित करने में विफल रहा कि क्या संपत्ति का कभी भी सहदायिकों के बीच विभाजन नहीं हुआ था। यह एक सर्वमान्य कानूनी सिद्धांत है कि दावा कोई सबूत नहीं है और इसलिए, वादी पर यह साबित करने का भार है कि संपत्ति का विभाजन अतीत में नहीं किया गया था, भले ही इसके विपरीत कोई लिखित कथन या खंडन का कोई साक्ष्य न हो। विचारण न्यायालय ने यह अनुमान लगाकर स्पष्ट रूप से एक गलत दृष्टिकोण अपनाया है कि केवल इसलिए कि इनकार या खंडन का कोई साक्ष्य नहीं था, वादी के मामले को साबित माना जा सकता है। इसलिए, विचारण न्यायालय को वादी-अपीलकर्ता की याचिका स्वीकार करते समय कारण अभिलिखित करना चाहिए था, भले ही वह एकपक्षीय साक्ष्य पर आधारित हो कि वादी वाद की संपत्ति की संयुक्तता को साबित

करने में सफल रहा था, जिसके आधार पर डिक्री की गई थी। विभाजन का प्रस्ताव उनके पक्ष में पारित किया जा सकता था।

16. उपरोक्त विश्लेषण और यहां अभिलिखत किए गए कारणों के परिणामस्वरूप, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को रद्द करना और मामले को सीमित सीमा तक प्रतिवादी-उत्तरदाता को लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति देने के बाद नए सिरे से सुनवाई के लिए विचारण न्यायालय में प्रेषित कर अपील की अनुमति देना कानूनी रूप से उचित था। परिणामस्वरूप अपील खारिज की जाती है। हालाँकि, हम इस तथ्य से अवगत हैं कि वादी/ अपीलकर्ता को अपनी ओर से बिना किसी गलती के भी प्रतिवादी के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में उलझने के लिए मजबूर किया गया है, जिससे इस न्यायालय के समक्ष अपील को जन्म दिया गया है, हालाँकि प्रतिवादी/ उत्तरदाता इसे दाखिल करने के कई अवसरों के बावजूद लिखित कथन दाखिल करने में विफल रहा और वादी गवाहों से जिरह करने में भी असफल रहा, लेकिन एक बार वादी/ अपीलकर्ता के पक्ष में आधे हिस्से के विभाजन का आदेश पारित होने के बाद, प्रतिवादी/ उत्तरदाता ने तुरंत इसे उच्च न्यायालय में अपील दायर कर चुनौती दी है। चूंकि विभाजन के मुकदमे का निपटारा अब मुकदमे की लंबी पुनर्सुनवाई में खिंच गया है, हम सांकेतिक लागत के रूप में पच्चीस हजार रुपये की राशि का अवार्ड देकर समानता और निष्पक्षता के पैमाने को संतुलित करना कानूनी रूप से

न्यायसंगत और उचित मानते हैं। प्रतिवादी/उत्तरदाता द्वारा वादी/ अपीलार्थी को शीघ्रता से भुगतान किया जाना चाहिए क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई का निर्देश देने वाला आक्षेपित आदेश उसके बाद ही प्रभावी होगा।

17. इस प्रकार प्रतिवादी/उत्तरदाता द्वारा वादी/ अपीलकर्ता को लागत का भुगतान करने की शर्त पर अपील खारिज कर दी जाती है।

बी.बी.बी. अपील खारिज

यह अनुवाद और्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्याम कुमार व्यास, (और.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण-यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादक और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।